निजी कंपनियों द्वारा घरेलू गैस (एल पी जी) की आपूर्ति

1809. **श्री रमा शंकर कैशिक:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कार्यरत निजी एल पी जी कंपनियों की संख्या कितनी है तथा क्या इन्हें भी अन्य सरकारी एल पी जी कंपनियों की तरह रसोई गैस वितरित करने की सरकार से अनुमति प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो निजी कंपनियां किस दर पर घरेलू गैस बेचती हैं सरकार ने किस स्थिति के तहत इन कंपनियों को अनुमति प्रदान की है;

(ग) क्या भारतीय एल पी जी वितरक परिसंघ ने सरकार पर एल पी जी को सीमा-शुल्क से छूट देने तथा रसोई गैस का बाजार भाव और अधिक बढ़ाने के लिए दबाव डाला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 93 में समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत निजी पक्षकारों को उनकी अपनी नीतियों के अनुसार बाजार निर्धारित कीमतों पर एल पी जी के समानान्तर विपणन की अनुमति दी। उन्हें देश में एल पी जी के आयात / विपणन के लिए सरकार से किसी अनुमति / अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

31.12.98 की स्थिति के अनुसार 140 निजी पक्षकारों ने एल पी जी विपणन के लिए श्रेणी प्रमाणपत्र प्राप्त किया था और इनमें से 84 पक्षकारों को संशोधित एल पी जी नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित एजेंसियों द्वारा जारी वैध श्रेणी प्रमाणपत्र प्राप्त हो गए हैं।

घरेलू उपभोक्ताओं को निजी पक्षकारों द्वारा बेची जा रही एल पी जी की दर प्रत्येक पक्षकार और स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। समानान्तर विपणन योनजा के अंतर्गत बेची जा रही एल पी जी की दर 15 रुपए और 20 रुपए प्रति कि०ग्रा० के बीच है।

(ग) और (घ) जी, नहीं

सरकार ने अपने 1999-2000 के बजट में क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों पर 27 / 28 फरवरी, 1999 की मध्यरात्रि से 2 प्रतिशत का विशेष आयात शुल्क हटा लिया है। इसके अलावा एल पी जी पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य, जो पहले राजसहायता कम करके 14 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया था, 6 रुपए प्रति सिलेंडर कम हो गया है और अन्य शहरों में यह कमी भाड़े और स्थानीय उद्ग्रहणों के आधार पर अलग-अलग है।

LPG Backlog in Tripura

1810. SHRI KHAGEN DAS: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Ministry has cleared the entire backlog of LPG applications in all other North-Eastern States except Tripura;

(b) if so, the reasons for leaving out Tripura; and

(c) by when does Government plan to clear the entire backlog in Tripura?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) Government has recently approved release of 1.5 lakhs additional LPG connections to clear the waiting list of Union Territories, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and North-East States including the State of Tripura. Public Sector Oil Companies have been asked to liquidate the entire waiting list of these states, which is expected to be cealred by end June, 1999.

Pilferage of Oil ONGC Wells

1811. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the systematic pilferage of oil from ONGC's wells at Ankleshwar and Gandhar in Gujarat;

(b) if so, how many cases of oil theft have been registered and how many culprits have been arrested so far;